

आज

बेबाक

हँसना सेहत के लिए अच्छा होता है। यही वजह है कि गुजरे जमाने में हास्य कलाकारों को लोग सिर माथे पर बिठाते थे। आज कॉमेडियनों को लोग गरियाते हैं। बहुत जल्द ये लतियाए भी जाएं तो ताजुब नहीं होगा। स्टैंडअप कॉमेडी के नाम पर अभद्र और आपत्तिजनक ही नहीं अश्लील शब्दों का भी डंके की चोट पर उपयोग होने लगा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बकने वाले कॉमेडियनों का बायकाट होना चाहिए। हास्य के नाम पर समाज में गंदगी फैलाने वाले इन वाहिदात कॉमेडियनों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान का भी सख्त जरूरत है।

टैरिफ पर कई देशों को छूट दे सकते हैं: ट्रम्प

वाशिंगटन (वार्ता) । अमेरिकी व्यापार भागीदारों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की 2 अप्रैल की समयसीमा करीब आने के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि वह टैरिफ पर कई देशों को छूट दे सकते हैं। श्री ट्रम्प ने सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, मैं कई देशों को छूट दे सकता हूँ, लेकिन यह पारस्परिक है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) ने ट्रम्प प्रशासन के साथ एक समझौते के तहत कार टैरिफ को 2.5 प्रतिशत तक कम करने पर सहमति व्यक्त की है। ट्रम्प ने आगे कहा, हम अगले कुछ दिनों में कुछ अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा करेंगे, जो ऑटोमोबाइल, कारों और सड़क के किनारे लकड़ी, लकड़ी और चिपस से संबंधित होंगे। ट्रम्प ने कहा, लेकिन अधिकांशतः 2 अप्रैल एक बड़ा दिन होगा, वह पारस्परिक दिन होगा, और हम उस धन में से कुछ धन वापस लाएंगे जो हमसे छीन लिया गया है।

भारत ने युनुस-मोदी बैठक का जवाब नहीं दिया

ढाका(वार्ता) । भारत ने अगले महीने की शुरुआत में बैंकॉक में होने वाले बिस्मटेक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगलादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनुस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच बैठक के लिए ढाका के अनुरोध पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ईरान वार्ता के लिए तैयार: अराघची

तेहरान (वार्ता) । ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराघची ने सोमवार को घोषणा किया कि उनका देश अमेरिका के साथ सीधे वार्ता में शामिल नहीं होगा, जब तक कि वाशिंगटन तेहरान के प्रति अपनी नीति में बदलाव नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए रास्ता खुला है।

इजरायली बंधकों ने गाजा में हमले रोकने किया आग्रह

गाजा (वार्ता) । हमास ने सोमवार को गाजा में बंधक बनाए गए दो इजरायली बंधकों का एक वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें इन बंधकों ने इजरायली सरकार से अपने सैन्य अभियान रोकने का आग्रह किया तथा चेतावनी दी कि लगातार हमले उनके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। टेलीग्राम पर हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा जारी किए गए वीडियो में बंधकों ने खुद को केवल कैदी नंबर 21 और कैदी नंबर 22 के रूप में पहचाना। उन्होंने दावा किया कि उनकी अपील स्वीच्छिक है और मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा नहीं है। एक बंदी ने 19 जनवरी के युद्ध विराम से पहले खाद्य पदार्थों की कमी के बारे में बताया और कहा कि जैसे ही युद्ध विराम के दौरान स्थितियां सुधर रही थीं, इजरायल ने 18 मार्च को अपना आक्रमण फिर से शुरू कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर झटका लगा। दोनों बंदियों ने चेतावनी दी कि जारी इजरायली हमलों से उनकी मौत हो सकती है और उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने पहले रिहा किए गए बंदियों से भी अपील की कि वे कैद के दौरान अपने अनुभवों को सार्वजनिक रूप से साझा करें।

गरमा-गरम

बिहार-बंगाल में चुनाव, BJP का ईद वाला दांव!

वित्त विधेयक 2025 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित

सालाना 12 लाख तक आय करमुक्त

अब चर्चा तथा वापसी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा



नयी दिल्ली (वार्ता) । लोकसभा ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के प्रावधानों में संशोधन के लिए वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार करते हुए वित्त विधेयक 2025 मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही 2025-26 के बजट को पारित करने की प्रक्रिया पर सदन की मोहर लग गई है। वित्त विधेयक को अब चर्चा तथा वापसी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा जहां उस पर मात्र औपचारिक चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत आयकर दाताओं की सालाना 12 लाख रुपये की आय पूरी तरह से करमुक्त होगी और उससे थोड़ा अधिक आय पर कर का प्रभाव सीमित रहेगा। उन्होंने गूगल और मेटा कंपनियों पर ऑनलाइन विज्ञापन की आय पर लगने वाले छह प्रतिशत की दर के इकालाइनजेशन कर को हटाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि 12 लाख से अधिक की थोड़ा अधिक आय पर लगने वाला कर बढ़ी हुई आय पर ही लगाया जाएगा और वह बढ़ी हुई आय तक ही सीमित होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि 12 लाख 10 हजार रुपये की आय होने पर आय के मामले

में दस हजार तक की आय पर ही आयकर लगाया जाएगा। उन्होंने आयकर में छूट के बावजूद वसूली में एक लाख करोड़ रुपये की वृद्धि पर उठाए गये सवाल के जवाब में कहा कि हमारा अनुमान व्यवहारिक है और पिछले कुछ साल से आयकर वसूली में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस साल के बजट में 13.13 लाख करोड़ से अधिक की प्राप्ति का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के बजट में व्यक्तिगत आयकर की प्राप्ति में करीब छह सात प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाते हुए अगले वित्त वर्ष में प्रत्यक्षकर वसूली में 13 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल मैप जैसे डिजिटल सोशल

भारत-भूमि की सनातन संस्कृति में जन्म होना हमारा सौभाग्य : सीएम यादव

बड़े नगरीय निकायों में 10-10 हजार गौ-वंश की क्षमता वाली बनाई जाएगी गौ-शालाएं

मुख्यमंत्री ने जन्मदिन पर सालरिया में सांधु-संतों एवं गौ-माता का लिया आशीर्वाद

मुख्यमंत्री ने जन्मदिन पर गौ-अभयारण्य में लगाया आंवले का पौधा

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत-भूमि की सनातन संस्कृति में जन्म होना हमारा सौभाग्य है। मेरा परम सौभाग्य है

भाजपा को मिल सकता है अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नया अध्यक्ष

नई दिल्ली(ए.) । अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भाजपा को नया अध्यक्ष मिल सकता है। भाजपा सूत्रों ने इसकी संभावना जताई है। दरअसल, संघ की बंगलूरु में संपन्न हुई तीन दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के अगले ही दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधि सभा की बैठक के तत्काल बाद दोनों नेताओं की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच संगठन चुनाव पर बातचीत हुई। गौरतलब है कि प्रतिनिधि सभा की बैठक में नड्डा ने संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी।



कि प्रदेश के सबसे बड़े गौ-अभयारण्य में जन्मदिन पर साधु-संतों एवं गौ-माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। गौ-हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित-

पल्लवित करते हैं, बल्कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सालरिया में गौ-माताओं का शुद्ध घी से बने 6100 लड्डुओं का पल्लवित करते हैं, बल्कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सालरिया में गौ-माताओं का शुद्ध घी से बने 6100 लड्डुओं का

न्यायाधीश नकदी मामला सभापति ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नयी दिल्ली (वार्ता) । राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के यहां बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के मुद्दे पर चर्चा के लिए सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। धनखड़ ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधाई कार्यों को पूरा करने के बाद सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह आज सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सदन के नेताओं से फिर मिलेंगे। इससे पहले उन्होंने सदन को बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नियम 267 के तहत एक नोटिस भी मिला है लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि सदस्य शून्य काल में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इस पर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। इस पर धनखड़ ने कहा कि यह मुद्दा न्यायिक अव्यवस्था से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह संसद की संप्रभुता, सर्वोच्चता और



प्रासंगिकता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, माननीय सदस्यों, इस सदन ने गरिमा को ध्यान में रखते हुए, गरिमापूर्ण आचरण का प्रदर्शन करते हुए, 2015 में सर्वसम्मति से एक कानूनी प्रणाली बनाई, और वह संवैधानिक संरचना जो संसद से एक अनुपस्थिति के साथ सर्वसम्मति से बनी, जिसे राज्य विधानसभाओं ने समर्थन दिया, वह कानून का शासन होना चाहिए क्योंकि इसे माननीय राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत अपने हस्ताक्षर करके अनुमोदित किया था। अब हम सभी के लिए इसे दोहराने का उपयुक्त अवसर है क्योंकि यह संसद द्वारा समर्थित एक दूरदर्शी कदम था। और कल्पना करें कि अगर ऐसा हुआ होता, तो चीजें अलग होतीं। सभापति ने कहा, माननीय संसद सदस्यों के लिए, मैं एक

भोग लगाया। उन्होंने सालरिया में 58 करोड़ 93 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 186 स्व-सहायता समूहों को 6 करोड़ 12 लाख रुपये का बैंक ऋण वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कन्या-पूजन कर उपहार भेंट किये। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को जन्मदिन पर गौ-अभयारण्य सालरिया (सुसनेर) में एक वर्षीय वेदलक्षणा महा-महोत्सव अन्तर्गत गौ-कथा उपसंहार **शेष पृष्ठ 5 पर**

रेखा गुप्ता ने पेश किया पहला बजट

एक लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव



बजट सत्र के दूसरे दिन प्रस्तुत बजट में बजट में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री गुप्ता जब बजट पेश

करने के लिए खड़ी हुईं, तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने सदन में मोदी-मोदी के नारे लगाए और मेज धपथा कर उनका अभिवादन किया। श्रीमती गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट न केवल दिल्ली के समग्र विकास के लिए नई राह खोलेगा, बल्कि हर क्षेत्र में उन्नति की संभावनाओं को मजबूत करेगा।

लोकार्पण-भूमिपूजन... मुख्यमंत्री ने 73 औद्योगिक इकाइयों को 441 करोड़ की निवेश प्रोत्साहन राशि प्रदान की

व्यापार में कमिटमेंट का है सर्वाधिक महत्व : सीएम यादव

प्रदेश में निवेश आ रहा है, उद्योग भी लग रहे हैं और रोजगार सृजित का सृजन कर विकास का लिखा जा रहा है नया अध्याय

मुख्यमंत्री ने 1127 करोड़ की लागत की औद्योगिक इकाइयों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बाबा महाकाल की कृपा से देश और प्रदेश में समृद्धि बरस रही है। सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली नगरी उज्जयिनी में पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ था। इसके बाद क्रमवार संभागीय

मुख्यालयों पर 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। इन आरआईसी में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन %विकसित भारत% को साकार करने प्रदेश में 1127.24 करोड़ रुपये के निवेश से 26 विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर विकास का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यह परियोजनाएं उज्जैन को एक नया औद्योगिक आयाम देंगी, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और आर्थिक विकास



होगा। इन इकाइयों से हमारे लगभग 5046 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो

के सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क विक्रम उद्योगपुरी में 28 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) का लोकार्पण भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को विक्रम व्यापार मेला उज्जैन में आयोजित औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि व्यापार वचन से होता है, व्यापार में वचन का ही सर्वाधिक महत्व है। मध्यप्रदेश सरकार औद्योगिकरण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिए गए वचनों को पूरा करने संपूर्ण रूप

से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से प्रदेश की 73 औद्योगिक इकाइयों को 441 करोड़ की निवेश प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आशीर्वाद से प्रदेश को नंबर 1 बनायेंगे। प्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने का जो सपना देखा है, वो साकार हो रहा है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर जिलों को मिलाकर एक नए मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा **शेष पृष्ठ 5 पर**

सीएम रेखा ने आयुष्मान जन आरोग्य से लेकर महिला समृद्धि योजना को बजट में दिया विशेष स्थान



नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में 2025-2026 का एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि इस बार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमारा फोकस होगा। आज ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली की नई सरकार ऐतिहासिक जनदेश के साथ आई है।

उन्होंने कहा कि यह बजट केवल सरकारी लेखा-जोखा नहीं है, यह दस साल से बेहाल दिल्ली का बजट है। यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली को खोखला कर दिया था। जनता को सिर्फ सपने दिखाए गए।

पूँजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव	दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैटीन खुलेगी	एमसीडी को 6897 हजार रुपये आवंटित किए गए	दिल्ली में सीएमश्री स्कूल खोले जाएंगे
बजट के दौरान सीएम रेखा ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं को रोका गया। विज्ञापन सरकार ने सिर्फ पोस्टर लगाए। दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा झुगियों में रहता है। हम मिलकर काम करने के इरादे से आए हैं। अब आपदा सरकार के दिन चले गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूँजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।	दिल्ली के बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लेने दिया। हमारी सरकार में अब लाभ मिलेगा। 20 करोड़ रुपये का आवंटित किया है। विधायक फंड पूरा मिलेगा। कोई कटौती नहीं होगी। भोजन कार्डों पर था। लेकिन हम देंगे। दिल्ली में 100 करोड़ रुपये से 100 जगहों पर अटल कैटीन खोली जाएंगी। अटल बिहारी बाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर कैटीन दिल्ली में खोली जाएंगी।	बजट पेश करने के दौरान सीएम रेखा ने कहा कि डीएम कार्यालय को जिला परियोजना कार्य के लिए 53 करोड़ रुपये, किसी भी आपदा को रोकने के लिए 30 करोड़ रुपए से कमांड ऑफिस के लिए दिया जाएगा। वहीं एमसीडी को 6897 हजार रुपये दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो और भी देंगे। वहीं दूसरी तरफ फायर फ़ाइटर और दमकल को बेहतर बनाने के लिए 100 जगहों पर छोटी फायर फ़ाइटर होगी। 110 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।	सीएम रेखा ने कहा कि एक नई परियोजना, 'NEEV – New Era of Entrepreneur Ecosystem and Vision' शुरू की जाएगी। इस पहल के तहत, बच्चों को आवश्यक कौशल के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीव परियोजना के लिए 20 करोड़ का बजट आवंटित किए गए हैं।
पर्यावरण और प्रदूषण पर ज्यादा जोर	<i>सरकार ने बजट में दिल्ली के पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर सतर्क दिख रही है। मुख्यमंत्री ने 506 करोड़ रुपए की मदद पर्यावरण को सुधारने के लिए आवंटित किए हैं तो वहीं दूसरी तरफ 300 करोड़ रुपये प्रदूषण से निजात के लिए आवंटित किए। बजट में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण पर जोर रहा है। एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम और ग्रीन कवर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आगे कहा कि हमारी सरकार दिल्ली में क्लाइमेट चेंज एयर</i>		
दिल्ली वालों को लंदन का सपना दिखाया: सीएम रेखा			
उन्होंने कहा कि एक समय था जब दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे। दिल्ली वालों को सपना दिखाया। लेकिन			

तब्बलीगी जमात के 10 नेपाली नागरिक डिपोर्ट

भोतिहारी(वार्ता)। भारत विरोधी प्रचार में शामिल तब्बलीगी जमात के 10 नेपाली नागरिकों को बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की रक्सौल सीमा से डिपोर्ट किया गया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ये सभी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। डिपोर्ट किए गए सभी नेपाली नागरिक राजस्थान में पकड़े गए थे। राजस्थान की दौसा पुलिस को इनके खिलाफ सूचना मिली थी कि कुछ नेपाली नागरिक भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। दौसा पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके खिलाफ आरोप सही पाया गया। सूत्रों ने बताया कि विदेशी नागरिक के भारत में प्रवास के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों का इन नेपाली नागरिकों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था। सभी 10 नेपाली नागरिकों को दौसा पुलिस ने हिरासत में लिया और उन्हें -लीव इंडिया नोटिस- देकर अपनी अभिरक्षा में रविवार को रक्सौल बॉर्डर से डिपोर्ट कर दिया। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दौसा के पुलिस उपाधीक्षक रविप्रकाश शर्मा ने संवाद एजेंसी -यूनीवार्ता- को बताया कि पांच लोगों को दौसा शहर से और पांच को पापड़वा से हिरासत में लिया गया था। इनमें से पांच पुरुष और पांच महिलाएं थीं। सभी नेपाली नागरिक थे। सभी पुरुष पापड़वा इलाके की एक मस्जिद में और उनकी पत्नियां दौसा के अलग-अलग घरों में रह रही थीं। ये सभी पिछले चार मार्च को रक्सौल सीमा से भारत में प्रवेश कर राजस्थान पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक डिपोर्ट किए गए लोगों में शहरदहीन अंसारी और उनकी पत्नी हलीमा खातून, मोहम्मद जान अंसारी और उनकी पत्नी सुलेखा खातून, रमजान अली मियां और उनकी पत्नी जफ्ना खातून, मोजाहिर हुसैन और उनकी पत्नी आयसा खातून एवं रज्जाक मियां और उनकी पत्नी रंखिया धोबिन शामिल हैं।

अमृतसर में दो ड्रग तस्करों का मकान ध्वस्त किया

अमृतसर(वार्ता)। पंजाब में अमृतसर जिला प्रशासन ने दो कुख्यात ड्रग तस्कर भाईयों अनवर गिल और अंधि के गांव गुमटाला, थाना कैटोनमेंट में स्थित मकान को ढहा दिया। पुलिस आयुक्त गुप्रीत सिंह मुख् ने मंगलवार को कार्रवाई की निगरानी की और ड्रग तस्करों को चेतावनी दी कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन तब तक कार्रवाई करता रहेगा जब तक कि गलत कामों में शामिल लोग सुधार नहीं जाते या पंजाब छोड़कर नहीं चले जाते।

इजराइली सेना ने सीरियाई ठिकानों पर सैन्य ठिकानों पर हमले का किया दावा

यरूशलेम(वार्ता)। इजराइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने सीरिया के तादमोर और टी4 स्थित सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने टेलीग्राम पर कहा, -कुछ ही समय पहले आईडीएफने तादमोर और टी4 में सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया।

टेस्ला के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई ‘आतंकवाद’ मस्क

वाशिंगटन(वार्ता/स्मूतनिक)। अमेरिकी अरबपति एवं 'स्पेसएक्स' के संस्थापक एलन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई को "आतंकवाद" बताया है। मस्क ने 'एक्स' पर कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि टेस्ला स्टोर में गोशियां चलाना और सुपरचार्जर को जलाना आतंकवाद की कार्रवाई है।

एमपी सीएम ने किया मोबाइल ऐप का लोकार्पण

भोपाल(वार्ता)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में जनसंपर्क विभाग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस ऐप से प्रदेशवासियों को सरकार की नीतियों, योजनाओं और महत्वपूर्ण समाचारों की त्वरित व सटीक जानकारी सीधे मोबाइल पर ही प्राप्त हो सकेगी।

विवादित टिप्पणी के बाद सुर्खियों में कामरा

एकनाथ शिंदे से माफी नहीं मांगूंगा, भीड़ से खौफ नहीं’ : कुणाल कामरा

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक फ़िल्मी गाने के सहारे विवादित टिप्पणी के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा लगातार सुर्खियों में हैं। शिवसेना सांसद समेत तमाम शिंदे समर्थकों का कहना है कि कुणाल को शिंदे से तत्काल माफ़ी मांगनी होगी। लगातार हो रही बयानबाजी के बीच कुणाल कामरा ने सोमवार देर रात अपना विस्तृत बयान जारी किया। कामरा ने कहा कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी विस्तृत बयान में कहा, 'मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी कह चुके हैं।'

सीएम फडणवीस ने कहा माफी मांगनी चाहिए

बकौल कामरा, अजित पवार भी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में 'गद्दारी' जैसी टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे इस भीड़ से नहीं डरते। कामरा ने कहा, वे अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शां होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। 36 वर्षीय कॉमेडियन की विवादस्पद टिप्पणी पर



कॉमेडियन कामरा ने नेताओं को दिया जवाब

कामरा ने उन नेताओं को भी जवाब दिया जिन्होंने उनसे माफ़ी मांगने को कहा है। अपने बयान के दूसरे हिस्से में कामरा ने लिखा, 'ये उन -राजनीतिक नेताओं- के लिए, है जो मुझे सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। बकौल कामरा, 'भले ही आज का मौडिया हमें कुछ और ही विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हो, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की प्रशंसा करने के लिए नहीं है।' उन्होंने कहा, 'अगर आप किसी मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर किया गया हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा यह अधिकार समाप्त हो जाएगा। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारे राजनीतिक तंत्र की आलोचना करना अवैध नहीं है। मैं पुलिस और अदालतों के साथ किसी भी वैध कानूनी कार्रवाई में सहयोग करने को तैयार हूं।'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कामरा को अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई पर सवाल करते हुए कामरा ने पूछा, 'क्या कानून समान रूप से उन लोगों के

बयान दिया। उन्होंने कहा, शायद वे अपने अगले शो के लिए एलिफ़्टन ब्रिज या मुंबई में किसी ऐसे जर्जर ढांचे को चुनना पसंद करेंगे, जिसे ध्वस्त किए जाने की जरूरत है।

भारत का अप्रैल में 10 अफ्रीकी देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास

नई दिल्ली। नौसेना के उपप्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने बताया कि भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फ़ोर्स संयुक्त रूप से इस अभ्यास को आयोजित करेंगे, जिसका नाम अफ्रीका-इंडिया मैरिटाइम एग्रेजमेंट (एआईकेईवाईएमई) है। यह अभ्यास तंजानिया के दार-एस-सलाम के तट पर होगा। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। अभ्यास छह दिनों तक चलेगा। इसमें कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या,

मेडागास्कर, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका समेत 10 अफ्रीकी देश हिस्सा लेंगे।

गौरतलब है कि यह कवायद पीएम नरेंद्र मोदी की वैश्विक दक्षिण के साथ जुड़ाव की विजन महासागर (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फ़ॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्स रीजन) के अनुरूप है। पीएम ने हाल ही में मॉरिशस यात्रा के दौरान इस विजन की घोषणा की थी।

नोटिस के 24 घंटे में मकान ढहाना गलत : सुको

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराने को गलत बताते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही, हैगनी जताई कि मालिकों को अपील करने का समय दिए बगैर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। शीर्ष अदालत ने कहा, वह प्रयागराज के याचिकाकर्ताओं एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों को सशर्त उनके खर्च पर पुनर्निर्माण की अनुमति देगा। जस्टिस अभय एस ओका व जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को शपथपत्र दाखिल करने का वक्त दिया। पीठ ने कहा, अगर वे संबंधित प्राधिकरण



के समक्ष तय समय में अपील करने का शपथपत्र देते हैं, तो वह उन्हें दोबारा घर बनाने की अनुमति देगा। इसका खर्चा उन्हें उठाना होगा। उन्हें शपथपत्र में लिखना होगा, वे भूखंड पर किसी भी तरह का दावा और किसी तीसरे पक्ष के हितों की बात नहीं करेंगे। पीठ ने यह भी कहा, अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है, तो

याचिकाकर्ताओं को अपने खर्च पर घरों को ध्वस्त भी करना होगा। याचिकाकर्ताओं को शपथपत्र दाखिल करने का समय देते हुए पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं वकील जुलफ़्कार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, दो विधवा महिलाएं और एक अन्य व्यक्ति ने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्हें 6 मार्च, 2021 को नोटिस दिया और 7 मार्च, 2021 को घर गिर दिए गए। वे इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, लेकिन ध्वस्तीकरण के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

जवाबदेही...

सुप्रीमकोर्ट ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी टास्क फोर्स गठित किया

छात्रों की बढ़ती आत्महत्याएं, न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों को लगाई फटकार

2018 से अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में 98 छात्रों ने आत्महत्या की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं न केवल व्यवस्था की विफलता को उजागर करती हैं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की ओर से संस्थागत सहानुभूति और जवाबदेही की गंभीर कमी को भी उजागर करती हैं। छात्रों की आत्महत्याओं पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान और आत्महत्याओं



को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया।

वकीलों के विरो

संवेदनशील प्रणाली की तत्काल आवश्यकता

2018 से उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याएं

आईआईटी - 39
एनआईटी - 25
केंद्रीय विश्वविद्यालय - 25
आईआईएम - 04
आईआईएसईआर - 03
आईआईआईटी - 02

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आत्महत्या को घटाने के लिए छात्रों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले विभिन्न कारकों से

निपटने के लिए एक मजबूत, व्यापक और उत्तरदायी तंत्र की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

आंखें खोल देने वाली याचिका

न्यायमूर्ति जे. ने दिल्ली पुलिस को 2023 में दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में पढ़ाई के दौरान आत्महत्या करने वाले दो छात्रों के परिवारों की शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। बी. पारदीवाला और जस्टिस. न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने यह आदेश दिया। आईआईटी दिल्ली में आत्महत्याओं के संबंध में याचिका

उन अभिभावकों के लिए आंखें खोलने वाली है जिनके बच्चे घर से दूर शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, साथ ही यह शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के लिए भी आंखें खोलने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या कहा गया है

बढ़ती आत्महत्याएं शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने और छात्रों को आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने से रोकने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की अपर्याप्तता और अप्रभावितता को दर्शाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस. आदेश में कहा गया है कि रबींद्र भट एनटीएफ के अध्यक्ष होंगे, जबकि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा कानूनी मामलों के सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे। एनटीएफ एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें छात्र आत्महत्याओं में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की पहचान, मौजूदा नियमों का विश्लेषण और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिफारिशें शामिल होंगी।

एक देश एक चुनाव' विधेयक पर बनी संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा



राज्यसभा से नए सदस्य का भी एलान

नई दिल्ली। लोकसभा ने मंगलवार को एक देश एक चुनाव को लेकर गठित संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी। अब इस समिति को कामरा की टिप्पणियों के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कुणाल के कटाक्ष की तुलना किसी के खिलाफबोलने के लिए 'सुपारी' लेने से की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कटाक्ष करते समय एक सिखाकर बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की वजह से प्रतिक्रिया होती है। शिंदे ने सोमवार को कामरा की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हमें भी व्यंग्य समझ में आता है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। शिंदे ने कहा, 'इसी व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, नरेश गोस्वामी और कुछ उद्योगपतियों पर टिप्पणी की थी। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। यह किसी के लिए काम करना है।

चर्चा करनी होगी, ऐसे में समिति का काम लंबा चलने की संभावना है। यही वजह है कि समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है।

संसदीय समिति में शामिल हैं 39 सदस्य

एक देश एक चुनाव के लिए दो विधेयक बीते साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किए गए थे। ये विधेयक हैं- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयकों का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए जरूरी बदलाव करना है। 12 दिसंबर को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इन विधेयकों को मंजूरी दी थी। हालांकि लोकसभा में विपक्ष के विरोध को देखते हुए लोकसभा में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूर कर लिया गया। लोकसभा के महासचिव ने सदन को ये भी बताया कि राज्यसभा से एक नए सदस्य को भी संसदीय समिति में जगह दी गई है। 39 सदस्यीय समिति में वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी के इस्तीफे के बाद एक पद खाली था। समिति के सदस्यों का मानना था कि उन्हें प्रस्तावित कानून के लिए बड़ी संख्या में हितधारकों से

सदन में कांग्रेस-बीजद विधायकों का हंगामा, कार्यवाही पांच बार स्थगित

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी कांग्रेस और बीजू जनता दल (बीजद) सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए घंटियां बजाई और नारे लगाए। हंगामा के चलते विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी को शाम चार बजे तक पांच बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन में बमुरिक्ल दो से तीन मिनट ही काम हो सका। बार-बार हंगामे के चलते उपसभापति भवानी शंकर भोई ने मामले को सुलझाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) द्वारा अपना फैसला बदलने से इनकार के चलते बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। सीएलपी ने स्पष्ट किया कि वे जून 2024 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ हुए सभी अपराधों की जांच के लिए सदन की समिति के गठन तक सहयोग



नहीं करेंगे।

बीजद ने न्याय दिलाने में सरकार की विफलता का विरोध किया

बीजद ने महिलाओं की सुरक्षा और एसटी-एससी व ओबीसी लोगों न्याय दिलाने में राज्य सरकार की कथित विफलता का विरोध किया। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण 18 मार्च से सभी कार्य दिवसों पर कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित हो रही है। दूसरी तरफ, भाजपा सदस्य बाबू सिंह ने कहा, 'विधानसभा के कामकाज के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे रोक रहा है।'

जैसे ही सदन की कार्यवाही

कांग्रेस विधायकों ने जांच समिति के गठन की मांग की

वहीं, कांग्रेस विधायकों ने पिछले नौ महीने में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए समिति के गठन की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना भी दिया।

शुरू हुई, बीजद और कांग्रेस के सदस्य तख्तियां लेकर वेल में आ गए। उन्होंने संगीत वाद्ययंत्र बजाए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। इस दौरान बीजद सदस्यों ने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर एकत्र होकर शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में एसटी-एससी और ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण की मांग की।

■ न्यूज गैलरी

नगर पालिका की सामान्य सभा की प्रथम बैठक आयोजित

कोण्डगांव/नवप्रदेश। नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरपति पटेल की अध्यक्षता में सामान्य सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में 1 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की अनुशंसा की गई। इसके तहत विकास नगर गार्डन के सौंदर्यीकरण हेतु निविदा जारी की गई। वहीं, शहर विकास योजना के तहत 30 करोड़ रुपये के कार्यों की कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में नगरपालिका क्षेत्र में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्णय लिए गए। नाितियों में कचरा फेंकने और सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा, ग्रीष्मकाल में मोटर पंप से पानी खींचने वाले लोगों के खिलाफकड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मोटर जब्त करने और नल कनेक्शन विच्छेद करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि जो दुकानदार लंबे समय से दुकान लेकर प्रीमियम राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनकी दुकानें निरस्त की जाएंगी। इसी तरह, सामुदायिक भवन को लेकर आई शिकायतों पर उसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया। नगर क्षेत्र में व्यावसायिक होड़िंग लगाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति लगाए गए होड़िंग पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर के गोठान का संचालन यादव गौसेना सेवा समिति को देने का निर्णय लिया गया।

भगवान आदिनाथ की जयंती मनाई गई

अंतागढ़। दिनांक 23 मार्च 2025 को सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा आदिनाथ भगवान के जन्मदिवस के अवसर पर भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती मनाई गई जिसमें जैन समाज के द्वारा बच्चों को उपनयन संस्कार संस्कार प्राप्त: कालीन किया गया जिसमें जैन समाज के संत मुनि श्री आगम सागर पुनोत सागर एवं जैन संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ शाम 4:00 बजे आदिनाथ भगवान की शोभायात्रा में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा एवं सकल जैन समाज के द्वारा नगर भ्रमण किया गया आदिनाथ भगवान के जन्म दिवस के अवसर पर पुरे नगर में मिठइयां बांटी गई एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी की चरण पादुकास्थापना पूर्व विधायक श्री अनुपनगर जी के द्वारा की गई,,,, इसमें सकल जैन समाज का सहयोग रहा।

करकेली में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन



बीजापुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप अंतिम व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं को पहुंचाने और उनके जीवन स्तर में व्यापक बदलाव लाने के जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा कलेक्टर सबित मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्य किए जा रहे इसी क्रम में भोपालपटनम के ग्राम करेपे अंतर्गत निर्धारित शिविर का आयोजन ग्राम करकेली में रखा गया उक्त शिविर में अनुभाग भोपालपटनम के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीईओ जनपद पंचायत, तहसीलदार के अलावा सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित हुए एवं करेपे पंचायत के 10 ग्रामों से ग्रामवासी ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिल एवं सायकल से उपस्थित होकर अपने समस्या संबंधित आवेदन पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, अन्य विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त किया गया। शिविर के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा दी गई और योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया गया।

नाबालिग का अपहरण करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

जगदलपुर। जिले के परपा थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले में 2 आरोपियों अनीश ठाकुर एवं दीपक ठाकुर को गिरफ्तार किया है। मामले में एक युवक ने एक नाबालिग से दोस्ती कर उसे प्यार के जाल में फंसाया। फिर बहला-पुसलाकर उसे अपने साथ ओडिशा ले गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने अपहृत नाबालिग को ओडिशा से बरामद कर लिया है। आरोपी अनीश ठाकुर उम्र 21 वर्ष निवासी जैतगिरी ने पूछताछ में बताया कि वह नाबालिग को शादी के लिए भगाकर ले गया था। पुलिस ने कुछ साक्ष्य जुटाए तो पता चला कि नाबालिग को आरोपी के साथ भगाने में दीपक ठाकुर उम्र 33 वर्ष का भी हाथ था।

प्रथम पेज का शेष

सालाना 12 लाख तक आय...

के पास है और इसकी रिपोर्ट इस सत्र के दौरान ही मिलने की उम्मीद है। वित्त विधेयक 2025 कदवाताओं को अनुरूपत कर राहत प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि अनुमानित आय पर कर (पीआईटी) संग्रह में उछल आने का अनुमान है। उन्होंने 2025-26 के बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनुमान व्यावहारिक है और इनमें करीब एक लाख करोड़ रुपये के छूट के प्रस्ताव को ध्यान में रखा गया है। यह कहना गलत है कि गाल और सेवाकर (जीएसटी) उगातिनीक कर नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले जीएसटी पर औसत दर 15 प्रतिशत थी जो घटकर औसतन 12.2 प्रतिशत पर आ गई है और 28 प्रतिशत की दर केवल सामान्य उपभोग की तीन प्रतिशत वस्तुओं पर ही लागू है। आम लोगों की सुविधा और उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी मुख्य रखा गया है। जीएसटी पर जीएसटी परिषद फैसला लेती है जो सैध्याधिक निवारण है। वहीं जीएसटी की दरों की संख्या तथा मात्रा को लेकर फैसला करती है।

उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे के लॉगर के सामान

कोण्डगांव/नवप्रदेश। भारत सरकार के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के दिशा में, आईटीबीपी (इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस) ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में बेडमाकोटी में एक नया कैंप स्थापित किया है। यह कैंप कुतुल से लगभग 5 किमी आगे स्थित है और इसे सुरक्षा बलों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। कोण्डगांव स्थित 41वीं वाहिनी, आईटीबीपी ने डीआईजी राणा युद्धवीर सिंह (सामरिक क्षेत्रीय मुख्यालय, भुवनेश्वर) के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

जिले में लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने 8 नए विद्युत उपकेन्द्रों की होगी स्थापना:कुणाल

कोण्डगांव/नवप्रदेश। जिले में लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन द्वारा आरखीएस योजना के तहत जिले में चार नए विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति मिली है, जिनमें कोण्डगांव विकासखण्ड के बोटीकनेरा और बोलबोला, माकड़ी विकासखण्ड के बालोण्ड और शामपुर शामिल हैं। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने इन उपकेन्द्रों के लिए राजस्व विभाग को सात दिनों के भीतर भूमि आबंटन करने के निर्देश दिए हैं।

इसके पहले कलेक्टर श्री दुदावत ने 33/11 केवी के लोहार पारा, पीपरा, लंजोड़ा रांधना में बनने वाले नए उपकेन्द्रों हेतु भूमि आबंटन प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत भूमि आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। साथ ही 132/33 केवी के जामगांव में भी एक उपकेन्द्र की स्थापना की जा रही है। लोहारा पारा, पीपरा, लंजोड़ा, रांधना, बोटीकनेरा, बालोण्ड, बोलबोला, शामपुर और जामगांव सहित सभी 08 नए उपकेन्द्रों के निर्माण से जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे नागरिकों को लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी। इस प्रकार जिले में बनने वाले

असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन हेतु काउंसलिंग 27 मार्च को

कांकर। जिले के बेरोजगार युवाओं के भविष्य को बेहतर एवं आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पखांजूर में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन (डेमेस्टिक) के 40 सीट हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना है। जिसके लिये 27 मार्च को सुबह 11 बजे से संस्था में काउंसलिंग आयोजित किया जायेगा। अत: इच्छुक उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास के साथ अंकव्युत्ती की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं 02 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा समस्त दस्तावेजों के मूल प्रति के साथ स्वयं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पखांजूर में उक्त तिथि में उपस्थित होंगे।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन का समय बदला

कांकर। प्रदेश में गर्मी की अधिकता के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मकाल की अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। आगामी 01 अप्रैल से 30 जून 2025 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन का समय 06 घण्टे से घटकर 04 घण्टे किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समयवधि में उक्त परिवर्तन करने पर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन प्रात: 07 से 11 बजे तक होगा।



बेडमाकोटी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां लगातार बनी रहेंगी। इसके बावजूद, यह कैंप न केवल नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत करेगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

जिले में लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने 8 नए विद्युत उपकेन्द्रों की होगी स्थापना:कुणाल



उपकेन्द्र सहित कुल 08 नये सब स्टेशन के निर्माण के साथ जिले के नागरिकों को लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है।

जिला प्रशासन द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन नए उपकेन्द्रों के निर्माण से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे नागरिकों को बिजली संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। जिला प्रशासन की इन पहलों से कोण्डगांव जिले में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता से प्राप्त

पुलिस ने चोरी के आरोपियों को किया गिरफ्तार

कोंडगांव/नवप्रदेश। माकड़ी पुलिस ने पानी टंकी में काम आने वाली सामान को चोरी करने वाले दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया ।

मिली जानकारी अनुसार दिनांक 10.09.2024 को प्रार्थी महोप सिंह पिता शेष प्रताप सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी महात्मा गांधी नगर गली नं. 05 अमलीडीह रायपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) कोण्डगांव द्वारा ग्राम उलेरा, कसरी, कावरा में पानी टंकी एवं पाईप लाईन कार्य अनुबाधित किया था। ग्राम पंचायत करमरी के पंचायत भवन के सामने ट्रेक्टर क्र0यूपी 70सीई 6164 स्कट पावर खड़ी किये थे जिसे रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ले गया प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपरधन क0 51/2024 धारा 303(2) बीएएस कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोण्डगांव के निर्देशानुसार एवं अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय कोण्डगांव व श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी

सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष अनुसंधान पर विडियो शो

कांकर। पैराडाइज हायर सेकेण्डरी सी.बी.एस.ई. स्कूल के कक्षा नर्सरी से ग्यारहवी कक्षा के छात्र-छात्राओं को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कें उनकी अंतरिक्ष जीवन के बारे में विडियो में जीवंत से जानकारी प्राप्त किया। उन्हें बताया गया कि सुनीता विलियम्स के द्वारा 9 महीने 14 दिन अंतरिक्ष में रहकर क्या-क्या रिसर्च किया। तथा वहां पर आने वाली चुनौतियों के बारे मे बताया गया।

बच्चों ने सुनीता विलियम्स के जीवन एवं उनके अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित प्रश्न पूछकर अपने जिज्ञासा और ज्ञान के स्तर को और अधिक बढ़ाया। उन्होंने जाना कि सुनीता विलियम्स स्पेसएक्स के डैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी में वापस कैसे आई। बच्चों ने जाना सुनीता विलियम्स ने इस मिशन के माध्यम से विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र मे एक नई उपलब्धि हासिल की है, उनकी यह यात्रा समूचे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। बच्चों ने यह भी जाना कि आज महिला आर्थिक,



सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक, खेल एवं विज्ञान के हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर परचम लहरा रही है, साथ ही महिलायें अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व स्थापित कर पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच रही हैं। छात्र-छात्राओं ने सुनीता विलियम्स के जीवन से तथा अंतरिक्ष विज्ञान स्पेश स्टेशन के बारे में बहुत ही बिस्तार से प्रेरणादायी जानकारी प्राप्त किया।

इस शिक्षा एवं अंतरिक्ष जीवन से प्रेरित कार्यक्रम को संपन्न कराने में प्राचार्य रश्मि रजक, उप प्राचार्य हरिन्द्र गोतुगुरी, एडमिनिस्ट्रेटर हमीद खान, कोऑर्डिनेटर पुनम जीत कौर वरिष्ठ शिक्षक प्रीति झा, पवित्र बरवाई, रूबी खान, दीपांजली गोंगोई, वर्षा रामानी, मेघा सेवा, शबाना परवीन, एस.मर्सी, तीर्थ

है। उन्होंने कहा कि जिस गांव में कोई विवाद न हों, जहां हर घर में गौ-माता हों, ऐसे गाँव को हम वृंदावन बनाएँ।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर-घर में गौवंश बंोने का निर्णय लिया है, इसके लिये निरंतर कार्य कर रही है, गौ-शालाओं को आहार अनुदान की राशि 20 रूपए से बंोकर 40 रूपए की गई है। जो व्यक्ति अपने घर में 10 से अधिक गौवंश पालेगा, उसे भी सरकार अनुदान राशि देगी। इसके साथ ही पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर पर 5 रूपए बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में अणु परीक्षण के जीवन से अणु परीक्षण संख्या में गाड़िया बिक रही है। अगले कुछ वर्षों में हम भव्य स्तर पर सिंहस्थ-2028 महापर्व का भी आयोजन करेंगे। आस्था का ये महाकुंभ अर्थव्यवस्था को गति देने में इतिहास लिखेगा और उज्जैन को प्रमुख वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा। इस वर्ष 4 लाख 21 हजार करोड़ रूपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है, जो आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करने के कार्य के लिए है। लाड़ली बहना हमारे प्रदेश का गौरव है, बजट में लाड़ली बहनों का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में अमृत द्वाघ दूध प्र-संस्करण का कारखाना भी स्थापित किया गया है। प्रदेश की

ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे

आईटीबीपी, भारत सरकार के नक्सल उन्मूलन मिशन के तहत, अबूझमाड़ क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। नए कैंपों की स्थापना से न केवल सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत हो रही है, बल्कि यहां के ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आईटीबीपी के हिमवीर न केवल क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय जनता को भारत सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं। इस निरंतर उपस्थिति से नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा है, जिससे आम जनता अब खुद को पहले से अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस कर रही है। डीआईजी राणा युद्धवीर सिंह ने कहा कि आईजी ओपी यादव (सेंट्रल प्रैंटियर, आईटीबीपी) के निरंतर मार्गदर्शन के कारण यह अभियान सफल रहा। उन्होंने 41वीं वाहिनी के सेनानी नरेंद्र सिंह और उनके हिमवीरों को बेडमाकोटी कैंप की सफल स्थापना पर बधाई दी।

‘बस्तर पंडुम’ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे

जिला स्तरीय कार्यक्रम 26 मार्च को सिंगारभाट कांकर में आयोजित

उत्तर बस्तर कांकर। बस्तर के संस्कृति संरक्षण हेतु राज्य शासन द्वारा “बस्तर पंडुम” का

आयोजन बस्तर संभाग के सभी जिलों में किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री नलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार गत दिनों जिले के विकासखण्डों में बस्तर पंडुम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला पंचायत के सीईओ श्री हर्शे मंडावी ने बताया कि बस्तर पंडुम में विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न आदिवासी समूहों के द्वारा प्राचीन लोकगीतों पर आधारित प्रस्तुति दी गई, जिसमें कांकर विकासखण्ड में आयोजित प्रतियोगिता में जनजातीय लोक नृत्य में धनकुल महिला पार्टी व्यासकोगेरा, जनजातीय लोक गीत में इरूंग पेन पसंग मांदरी लोक नृत्य पार्टी तुलतुली, जनजातीय वाद्ययंत्रों वेशभूषा एवं आभूषण प्रदर्शन में बेलोसा दुलोसा लया गुप बागोडार, जनजाति कला एवं गोदना में जंगो रायतार महिला समूह इसी प्रकार चारामा विकासखण्ड में आयोजित जनजातीय लोक नृत्य में नोमेश्वर कुजाम एवं दल, जनजातीय लोक गीत में बालक आश्रम सिरिसिदा, जनजाति वाद्ययंत्रों में जय सोन्दर्य गन्धर्व बाजा पार्टी बरकछार, जनजाति वेशभूषा एवं आभूषण में कन्या आश्रम पण्डरीपानी, जनजाति कला एवं गोदना में कु. थामेश्वरी मंडावी, जनजाति पेय पदार्थ एवं व्यंजन में श्रीमती कांती केदारी तथा नरहरपुर में आयोजित प्रतियोगिता में जनजातीय लोक नृत्य में कचना ध्रुवा आदिवासी मांदरी नृत्य, जनजातीय लोकगीत में जय गांडवाना रेला पाटा थीम, जनजाति वाद्ययंत्रों में धनेश्वरी मंडावी एवं साथी, जनजाति वेशभूषा एवं आभूषण प्रदर्शन में जोहार टीबल इंडिया, जनजाति शिल्प एवं चित्रकला में आदिवासी ओझा गोदना कला, जनजाति पेय पदार्थ में लक्ष्मी उसेण्डी बारादेवी विजेता रही।





रायपुर/नवप्रदेश। आकाशवाणी रायपुर के द्वारा प्रसारित नमस्ते रायपुर कार्यक्रम के अंतर्गत आज 26 मार्च 2025 को विजय मिश्रा 'अमित' की भेंट वार्ता का प्रसारण प्रातः 7:30 बजे किया जाएगा। आकाशवाणी के प्रोग्राम एजीक्यूटिव प्रकाश उदय इस कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ प्रहरी संस्थान के संस्थापक पशु प पर्यावरण प्रेमी विजय मिश्रा से साक्षात्कार करेंगे। पर्यावरण पशु प संरक्षण के लिए मिश्रा द्वारा विगत 35 वर्षों से कारगर प्रयास किए गए हैं इस हेतु उन्हें ग्रीन इडोल, प मित्र सहित अनेक पुरस्कार मिले हुए हैं। पेड़ों के पापा और चिड़ियों के चाचा जैसे निक नाम से भी उन्हें जाना जाता है।

महापौर और सभापति ने कर्मा जयन्ती की शुभकामनाएं दी

रायपुर/नवप्रदेश। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे और सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने सभी नगरवासियों विशेषकर साहू समाज के अनुयायियों को साहू समाज की कुल देवी महाप्रभु जगन्नाथ की परम भक्तिनी समाज सुधारक, धर्मात्मा, परोपकारी भक्त माता कर्मा की जयन्ती मंगलवार दिनांक 25 मार्च 2025 के अवसर पर अग्रिम हार्दिक शुभकामनायें देते हुए सभी नगरवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शान्ति प्रदान करने हेतु और रायपुर को स्वच्छ, सुन्दर, हरित, विकसित और सुव्यवस्थित नगर बनाने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्रदान करने हेतु साहू समाज की कुल देवी और महाप्रभु जगन्नाथ की परम भक्तिनी भक्त माता कर्मा के चरणों में विनम्र प्रार्थना की है। नगर निगम महापौर मीनल चौबे और सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 के अंतर्गत सभी नगरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में रायपुर नगर के हित में स्वच्छता एप्प डाउनलोड कर मोबाइल पर स्वच्छता फीडबैक देने की विनम्र अपील की है ।

प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। 1 और 2 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी।50 हजार से अधिक सीटों पर दाखिला - प्रदेश में इस साल 6,744 निजी स्कूलों में कुल 50,413 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा।।नेडल अधिकारी 25 अप्रैल तक जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे। लॉटरी के माध्यम से 1 और 2 मई को सीटों का आवंटन किया जाएगा. यह प्रक्रिया 5 से 30 मई तक चलेगी। कैसे करें आवेदन ?आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए माता-पिता शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसकेअलावा आधिकारिक ऑनलाइन सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते। प्राइवेट स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में 51,293 सीटों में अगर सीटें खाली रह जाती है तो उन संबंधित स्कूलों में प्रवेश के लिए दोबारा से आवेदन मांगे जाएंगे। दूसरे चरण में पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। दस्तावेजों की जांच के बाद निजी स्कूलों में एडमिशन मिल सकता है।

भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव : 26 मार्च से शुरू होगी 15 दिवसीय प्रभात फेरी

रायपुर। भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव राजधानी में भव्यता के साथ मनाया जा रहा है. उत्सवों के क्रम में सोमवार को डॉ. अम्बेडकर अस्पताल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह के बेसमेंट में गोल्ड ऐज रूप और जैन युवा महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 13 दिवसीय भोजन वितरण कार्यक्रम का आगाज किया गया. यह कार्यक्रम 6 अप्रैल तक चलेगा, जिसके अंतर्गत सोमवार को अंबेडकर अस्पताल परिसर में जरूरतमंदों और मरीजों के परिजनों को भोजन वितरण किया गया.भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम प्रभात फेरी 26 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है. यह 15 दिवसीय प्रभात फेरी कार्यक्रम 9 अप्रैल तक चलेगा, जिसके अंतर्गत शहर के अलग-अलग क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली जाएगी. भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव समिति 2025 के अध्यक्ष महावीर कोचर, महासचिव सिद्धार्थ डगगा एवं कोषाध्यक्ष वीरेंद्र डगगा ने बताया कि पूरे 15 दिनों तक प्रभात फेरी निकलेगी और समापन स्थल पर हर दिन जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लड, शुगर, सीबीसी और थायरॉइड टेस्ट किया जाएगा.प्रभात फेरी प्रतिदिन सुबह 6.30 बजे निकलेगी

उड़ान...

रायपुर से शुरू होगी विशाखापट्टनम के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए विशाखापट्टनम अब नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। बजट एयरलाइंस इंडिगो ने रायपुर-विशाखापट्टनम-रायपुर सेक्टर में 31 मार्च से नई फ्लाइट शुरू करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश के कारोबारी, विद्यार्थी और पर्यटक लंबे समय से इस रूट पर सीधी फ्लाइट की मांग कर रहे थे। रायपुर से इंदौर, भोपाल, प्रयागराज के लिए भी नई उड़ानें



इंडिगो एयरलाइंस ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से इंदौर, भोपाल और प्रयागराज के लिए भी नई फ्लाइट्स शुरू करने की

योजना बनाई है. इन उड़ानों के शुरू होने से इंदौर, भोपाल और प्रयागराज के फेयर भी सस्ते होंगे। इंदौर-रायपुर-इंदौर फ्लाइट 30

मार्च से प्रतिदिन चलेगी। रायपुर-प्रयागराज-रायपुर फ्लाइट 30 मार्च से शनिवार और रविवार को उड़ान भरेगी।

भोपाल-रायपुर-भोपाल फ्लाइट 30 मार्च से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी।

शेड्यूल जारी, मात्र 3000 रुपए होगा किराया

रायपुर से शुरू होगी विशाखापट्टनम के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट



इंडिगो की यह फ्लाइट सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को संचालित होगी. यात्रियों की सुविधा के लिए 78 सीटर एटीआर विमान लगाया गया है. इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का सफर सिर्फ डेढ़ घंटे में पूरा होगा. शुरुआती दौर में 31 मार्च को रायपुर से विशाखापट्टनम की टिकटें मात्र 3,000 रुपये में उपलब्ध हैं। विशाखापट्टनम स्वास्थ्य सेवाओं, एजुकेशन, वीकेंड टूरिज्म और वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में लोकप्रिय है. इस फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

सप्ताह में पांच दिन उड़ान सेवा

इंडिगो की यह फ्लाइट सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को संचालित होगी. यात्रियों की सुविधा के लिए 78 सीटर एटीआर विमान लगाया गया है. इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का सफर सिर्फ डेढ़ घंटे में पूरा होगा. शुरुआती दौर में 31 मार्च को रायपुर से विशाखापट्टनम की टिकटें मात्र 3,000 रुपये में उपलब्ध हैं। विशाखापट्टनम स्वास्थ्य सेवाओं, एजुकेशन, वीकेंड टूरिज्म और वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में लोकप्रिय है. इस फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

मार्च से प्रतिदिन चलेगी।

रायपुर-प्रयागराज-रायपुर फ्लाइट 30 मार्च से शनिवार और रविवार को उड़ान भरेगी।

भोपाल-रायपुर-भोपाल फ्लाइट 30 मार्च से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी।

छात्र-छात्राओं का लैंप लाइटिंग एवं शपथ ग्रहण समारोह

ट्ट उज्ज्वला -5th लैंप लाइटिंग एवं शपथ ग्रहण समारोह और एडवांस रिकल लेब का उद्घाटन

रायपुर/नवप्रदेश। श्रीरावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च नया रायपुर परिसर में स्थित रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में बी.एस. सी. नर्सिंग 2020-2021 से 2023-2024 बैच के छात्र-छात्राओं का लैंप लाइटिंग एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कैपस परिसर ने धूमधाम से किया गया।

सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉ.पी.के. पात्रा कुलपति पं. दीन



दयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, एस. एस. बजाज सर माननीय कार्यकारी निदेशक रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, प्रमोद पांडे सर, निदेशक नर्सिंग - रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नर्सिंग महाविद्यालय की प्रचार्या अपर्णा सिंह मैम ने मां



द्वारा माननीय कार्यकारी महोदय एवं नर्सिंग प्रचार्या द्वारा निदेशक नर्सिंग का स्वागत एवं सम्मान पौधा भेंट एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया मुख्य अतिथि डॉ. पात्रा ने अपने उद्बोधन में नर्सिंग शिक्षा में योगदान के लिए महाविद्यालय की सराहना की और स्किल आधारित शिक्षा देने की मांग रखी एवं छात्र

महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को अपनी उपलब्धियों से महाविद्यालय को गौरवान्वित करने हेतु पुरस्कृत किया गया जिसमें महाविद्यालय के बी. एस.सी. नर्सिंग प्रथम बैच की छात्रा चांदनी पटेल एवं बी. एस.सी. नर्सिंग 4ह्रद्ध बैच की छात्रा प्रतिभा साहू को क्रमशः ्रद्धस्स रायपुर एवं ्रद्धस्स भुवनेश्वर में नर्सिंग ऑफिसर पद कर चयन हेतु स्टूडेंट्स एलुमनी-अवॉर्ड फॉर हाइयर अचीवमेंट से पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात सभी छात्रों में कैडल थाम कर कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा की शपथ ली।अगली कड़ी में नीतू त्रिपाठी मैम ने महाविद्यालय के छात्रा मन्नाएं दी।कार्यक्रम की अगली कड़ी में

निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री साय जल्द लेंगे फैसला : साव

ट्ट जिला और मंडलों में भी होगा कार्यसमिति का गठन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निगम-मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चल रही अटकलों के बीच डिटी मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। आज एक प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संघ्न हो चुके हैं, अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही इन नियुक्तियों पर फैसला लेंगे।

डिटी सीएम ने बताया कि भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा के बाद निगम-मंडलों में नियुक्तियां तय की जाएंगी। इसके साथ ही जिला और मंडलों में भी कार्यसमिति का गठन जल्द किया जाएगा। संगठन विस्तार और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पेयजल संकट से निपटने करेंगे हरसंभव उपाय : डिटीसीएम : गमी बढ़ते ही जल संकट गहराने लगा है। राज्य कई इलाकों में जल स्तर नीचे गिरने और बारिश की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेयजल आपूर्ति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। इसे लेकर उम्मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में कुछ आंशिक बारिश होती है, जो इस

बार नहीं हुई। ऐसे में अभी से ही गमी का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिससे जल संकट गहराने की आशंका है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने जल संसाधन, ऊर्जा एवं यांत्रिकी, और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गमी में लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो, इसके लिए हरसंभव उपाय किए जाएं। जखरूत के अनुसार नए ट्यूबवेल और हैंडपंप लगाए जाएं। साथ ही, तालाबों में जलभराव और निस्तारी के लिए भी योजना बनाई जाए।

अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर साव का तंजः कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में होने जा रहा है, जहां पार्टी की भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। इस पर डिटी मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब शून्य की ओर बढ़ रही है और उसका भविष्य सबको दिख चुका है। छत्तीसगढ़ में औद्योगीकरण को मिलेगी रफ्तारः राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की है, जिसमें रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। इसी कड़ी में बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग को 18 लाख का चूना लगाने वाला बाबू गिरफ्तार

ट्ट खुद के और रिश्तेदारों के खाते में जमा किए थे आकाश ने विभाग के पैसे

रायपुर/नवप्रदेश। उच्च शिक्षा विभाग को 18 लाख रुपए का चूना लगाने वाले आरोपी क्लर्क आकाश श्रीवास्तव को रायपुर पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। विभागीय जांच में अफ़ा-तफ़ी के खुलासे के बाद आरोपी क्लर्क के खिलाफ अपर संचालक ने सरस्वती नगर पुलिस थाना में एफ़आईआर दर्ज कराया था। मिली जानकारी के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग के रीजनल ऑफिस में पदस्थ ग्रेड 2 क्लर्क आकाश श्रीवास्तव ने 2023 से 2025 के बीच पद पर



रहते हुए 18 लाख रुपए सरकारी राशि का अपने व रिश्तेदारों के खाते में जमाकर निजी उपयोग किया था। उच्च शिक्षा विभाग को जब क्लर्क की हरकतों का पता चला तो पहले 11 मार्च को निलंबित किया गया, इसके बाद 18 मार्च को उसके खिलाफ आनन-फ़ानन में सरस्वती नगर थाने में अपराध दर्ज कराया गया था। दरअसल, आकाश श्रीवास्तव ने सुनियोजित तरीके

से कूटरचना कर शासकीय धन को विभिन्न बैंक खातों में फर्जी तरीके से जमा किया और बाद में उन पैसों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से ट्रांसफर कर लिया। अपने बैंक खातों के अलावा आरोपी ने दो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के खातों में भी शासकीय धन को गबन करने के लिए जमा करने के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिया था।

भाजपा सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी : कांग्रेस

बिलासपुर, रायपुर, जशपुर, बस्तर में धर्मांतरण की घटनाओं पर सरकार जवाब दें

रायपुर/नवप्रदेश। भाजपा के राज में धर्मांतरण की घटनाये बढ़ गयी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिलासपुर, रायपुर, जशपुर, बस्तर में धर्मांतरण की घटनाओं पर सरकार जवाब दें। धर्मांतरण भाजपा के लिये राजनैतिक हथियार वह निदान नहीं चाहती। भाजपाई ही संरक्षण देते है और दिखावे के लिए शिकायत भी करते है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने अपनी पहली बैठक में ही वह दावा किया था कि नया -धर्म स्वातंत्र विधेयक- का ड्राफ्ट तैयार



है, 60 दिन के भीतर लागू हो जायेगा, लेकिन सवा साल से अधिक बीतेने के बाद आज तक मौन है। अब भी भाजपा के मंत्री केवल कह ही रहे है कि नया कानून लागेगे, हकीकत यह है कि राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है प्रदेश के शहरी एवं मैदानी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण की घटनायें बढ़ गयी है। भाजपा खुद धर्मांतरण को बढ़ावा देती है फिर वर्ग संघर्ष

करवाती है विपक्ष में रहते हुये धर्मांतरण के नाम पर फ़साद करने वाले भाजपाई पिछले एक साल से प्रदेश में होने वाली धर्मांतरण की घटनाओं पर चुपची साध लिये है। यही नहीं खबरें तो यह भी आ रही है कि धर्मांतरण कराने वालों को सत्तारूढ़ दल का संरक्षण मिला हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, जशपुर, बस्तर में धर्मांतरण की घटनाओं के बाद भाजपा की खामोशी इस बात का प्रमाण है कि इन घटनाओं को उसका समर्थन है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जबरन धर्मांतरण को सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिये बड़ी समस्या बताया था।

न्यूज गैलरी

को-सीईओ हान जोंग-ही का दिल का दौरा पड़ने से निधन

नई दिल्ली । दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने मंगलवार को अपने को-सीईओ हान जोंग-ही के आकस्मिक निधन की जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि 63 वर्षीय हान जोंग-ही का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह सैमसंग के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल डिवाइस डिवीजन का नेतृत्व कर रहे थे। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि हान जोंग-ही छुट्टी पर थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कंपनी ने अभी तक उनके उत्तराधिकारी के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। हान जोंग-ही ने लगभग 40 साल पहले सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना करियर शुरू किया था और उन्होंने कंपनी के टेलीविजन व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी विशेषज्ञता के चलते उन्हें 2022 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का वाइस प्रेसीडेंट और को-सीईओ नियुक्त किया गया था। वह कंपनी के बोर्ड के सदस्य भी थे। उनका निधन ऐसे समय में हुआ है जब सैमसंग हाल के कुछ तिमाहियों में कमजोर मुनाफे और शेयर की गिरती कीमतों से जूझ रही है। कंपनी एडवांस्ड मेमोरी चिप्स और कांटेक्ट चिप मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ रही है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ट्यू) परियोजनाओं के कारण इन क्षेत्रों में मांग में तेजी आई है। इसके अलावा, स्मार्टफोन बाजार में भी एप्पल ने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है। सेमीकंडक्टर सेगमेंट में सैमसंग, एसके हाइनिक्स से पीछे है, जो एनवीडिया जैसी कंपनियों को एआई ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (त्नक) के लिए एचबीएम चिप्स की आपूर्ति करता है। पिछले हफ्ते हुई शेयरधारकों की बैठक में हान जोंग-ही ने कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन पर खेद व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था, हमारे शेयरों के प्रदर्शन पर मैं क्षमा चाहता हूं। पिछले साल, हम एआई सेमीकंडक्टर बाजार में तेजी से हो रहे बदलावों पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पाए।

कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की छोटी सिप-सपनों को साकार करने का छोटा सा तरीका

मुंबई । कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ("KMAMC" / "कोटक म्यूचुअल फंड") ने आज ःछोटी सिप सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है। छोटी सिप कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की सभी पात्र योजनाओं के लिए उपलब्ध होगी।* हाल ही में सेबी और एएसएफआई ने छोटी सिप (स्मॉल टिकट एसआईपी) की शुरुआत की, जिससे भारत के और अधिक लोगों को धन सृजन की यात्रा में शामिल होने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर निलेश शाह ने कहा, ःभारत की कुल आबादी में से केवल 5.4 करोड़ युनिक इन्वेस्टर ही म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जिससे देश में म्यूचुअल फंड के व्यापक विस्तार की बड़ी संभावना है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) नए निवेशकों को जोड़ने और उनकी म्यूचुअल फंड यात्रा शुरू करने का एक शानदार तरीका रहा है। छोटी सिप के लॉन्च के साथ, कोई भी नया निवेशक केवल ७250 की न्यूनतम राशि से अपनी संपत्ति निर्माण की यात्रा शुरू कर सकता है।

90 लाख करदाताओं ने फाइल किया अपडेटेड

नई दिल्ली । हाल ही में संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जिससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। यह सरकार द्वारा शुरू की गई वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम की सफलता को दर्शाता है। सरकार ने 2022 में स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने की योजना के तहत अतिरिक्त आयकर का भुगतान करदाताओं के लिए किसी स्पेसिफिक असेसमेंट इंयर से दो साल तक अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का विकल्प पेश किया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कुल मिलाकर, असेसमेंट इंयर 2021-22 से असेसमेंट इंयर 2024-25 के बीच 9.176 मिलियन से अधिक आईटीआर-यू फाइल किए गए।

टियर 2 और 3 शहरों में हुए सबसे ज्यादा लेनदेन

2024 :भारत में होटल ट्रांजैक्शन 2,900 करोड़ रुपये तक पहुंचा

मुंबई । भारत में 2024 में होटल ट्रांजैक्शन 2,900 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसमें दिलचस्प बात टियर 2 और 3 शहरों से जुड़ी देखी गई। मंगलवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार होटल ट्रांजैक्शन के तहत टियर 2 और 3 शहरों में 50 प्रतिशत लेनदेन हुए। इनमें मुख्य रूप से बिना बांड वाली मध्यम श्रेणी की होटल शामिल हैं।

जेएलएल की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाई-नेट वर्थ इंडिविजुअल (एचएनआईएस), फैमिली ऑफिस और निजी मालिकों ने निवेश मात्रा में 51 प्रतिशत का योगदान दिया। 2024 की चौथी तिमाही में, भारतीय आतिथ्य क्षेत्र (इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर) ने मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन किया, जिसमें टॉप छह बाजारों में एक्वेज डेली रेट (एक्वीआर) और रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम (रेवपीएआर) दोनों में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई।

हैदराबाद सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला शहर रहा, जिसने 23.3 प्रतिशत की उच्चतम रेवपीएआर वृद्धि दर्ज की, जो एडीआर में वृद्धि की वजह से देखी गई। बेंगलुरु में भी उच्च रेवपीएआर वृद्धि दर्ज की गई, जो कि एडीआर और ऑक्यूपेंसी रेट दोनों में सुधार की वजह से रही। इस तिमाही में होटल साइनिंग में पर्याप्त गतिविधि देखी गई, जिसमें 99 नए होटलों में कुल 11,943 चाबियां दी गईं।

जेएलएल के होटल और आतिथ्य समूह के भारत प्रबंध निदेशक जयदीप खंग ने कहा, हमने पिछले साल 367 नए होटलों के साइनिंग और 154 नए होटलों का उद्घाटन रिकॉर्ड किया। यह 2023 की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। यह होटल इंडस्ट्री इकोसिस्टम के लिए उत्साहजनक खबर है, क्योंकि यह निर्माण और ऋण गतिविधि को



बढ़ावा देगा और आखिर में पूरे स्पेक्ट्रम में रोजगार प्रदान करेगा। यह भारतीय आतिथ्य बाजार में निवेशकों के निरंतर विश्वास और

विस्तार को भी दर्शाता है।मिडस्केल सेगमेंट ने 53 प्रतिशत होटल ओपनिंग और 44 प्रतिशत साइनिंग के साथ दबदबा बनाया। उत्तर प्रदेश

1,744 चाबियों के साथ साइनिंग में सबसे आगे रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के यशोभूमि और मुंबई के एयरपोर्ट जिले में नए हॉटस्पॉट उभर रहे हैं, जो इन क्षेत्रों में भविष्य में विकास की संभावना का संकेत देते हैं।कुल मिलाकर, 2024 की चौथी तिमाही ने एक मजबूत और विस्तारित भारतीय आतिथ्य बाजार की तस्वीर पेश की, जिसमें विभिन्न शहरों, स्तरों और खंडों में विकास फैला हुआ है, जो उद्योग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देता है। खंग ने कहा, भारत में आतिथ्य बाजारों में 2024 में शानदार गतिविधि देखी गई। बिजनेस और लेजर दोनों सेगमेंट में मजबूत घरेलू यात्रा मांग के सपोर्ट से होटल निवेश ने कई नए समूहों को खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में नए होटल बनाने की ओर आकर्षित किया।

बीते 10 वर्षों में देश में दालों का निर्यात, आयात की अपेक्षा तेजी से बढ़ा

दालों में आत्मनिर्भर बन रहा भारत, एनडीए सरकार में आयात के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा निर्यात



नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर विजन के तहत भारत दालों में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में दालों का निर्यात, आयात की अपेक्षा तेजी से बढ़ा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का दालों का निर्यात वित्त वर्ष 25 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 4,437 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 15 में यह 1,218 करोड़ रुपये था।

इस तरह, बीते 10 वर्षों में भारत का दाल निर्यात 264.29 प्रतिशत बढ़ा है।दूसरी तरफ, इस दौरान आयात में 86.45 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। देश में वित्त वर्ष 25 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 31,814 करोड़ रुपये की दालों का आयात किया गया है। वहीं, वित्त वर्ष 15 में यह आंकड़ा 17,063 करोड़ रुपये था।वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के शासनकाल

के 10 वर्षों में दालों के निर्यात में 187.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और आयात में 457.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ था।वित्त वर्ष 14 में भारत ने 1,749 करोड़ रुपये की दालों का निर्यात किया था। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 05 में 608 करोड़ रुपये था।यूपीए के

शासन में वित्त वर्ष 14 में भारत ने 11,037 करोड़ रुपये की दालों का आयात किया था। वहीं, वित्त वर्ष 05 में यह आंकड़ा 1,981 करोड़ रुपये पर था।भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है।

रायपुर में फूड डिलीवरी के मामले में स्विगी की बोल्ट सर्विस ने किया शानदार विकास

रायपुर/नवप्रदेश। भारत के अग्रणी ऑन-डिमांड कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म स्विगी ने आज रायपुर में अपनी बोल्ट सर्विस (बोल्ट बाय स्विगी) के शानदार विकास के आंकड़े साझा किए। यह क्विक फूड डिलीवरी सर्विस शहर में लोगों के खाने के तरीके को बदल रही है। ऑर्डर्स में मासिक आधार पर 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे रेस्टोरेंट्स को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिल रही है। बोल्ट बाय स्विगी के माध्यम से 10 मिनट के अंदर प्रेश फूड की डिलीवरी की जाती है। सुपर-स्मार्ट बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन के दम पर यह संभव हुआ है। रायपुर के 30 प्रतिशत रेस्टोरेंट इस सर्विस से जुड़ चुके हैं। शहर के खाने के शौकीन लोग ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर और लेट नाइट बाइट्स के दौरान 5,000 से ज्यादा आइटम्स में से ऑर्डर कर

सकते हैं। सभी डिलीवरी को टॉप स्पीड में ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। उल्लेखनीय रूप से बोल्ट के ऑर्डर्स में 39 प्रतिशत हिस्सेदारी डिनर की और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी लंच की रही।

स्विगी की बोल्ट सर्विस केवल स्पीड की बात नहीं है, बल्कि यह स्मार्ट ऑपरेशंस एवं ज्यादा खुश ग्राहकों की बात भी है। इसके माध्यम से रेस्टोरेंट्स का वर्कफोल्ड बेहतर हुआ है, इंतजार का वक्त कम हुआ है और रिपीट ऑर्डर्स में बढ़ोतरी देखी गई है। होटल हैदराबादी, जूस जंगल, नेताजी होटल और थाली एक्सप्रेस जैसे प्रसिद्ध स्थानीय ब्रांड्स ने पर यह संभव हुआ है। रायपुर के 30 प्रतिशत सर्विस से जुड़कर इनके रोजाना के ऑर्डर्स में वृद्धि दर्ज की गई है। बोल्ट सर्विस इनके लिए महत्वपूर्ण रेवेन्यू ड्राइवर के रूप में सामने आई है।

अमेरिका से व्यापार समझौते पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत

नई दिल्ली । भारत के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से किए गए किसी भी व्यापार समझौते को कांग्रेस में संशोधन या अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच जीटीआरआई नाम आर्थिक थिंक टैंक ने भारतीय अधिकारियों को बातचीत में सावधान रहने की सलाह दी है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के दौरान भारत को सावधान रहना होगा, क्योंकि अमेरिका में फास्ट ट्रेड ट्रेड अथॉरिटी नहीं होने के कारण समझौते में किसी भी बड़े बदलाव के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (तन्नत्रष्टु) ने दोनों देशों के बीच व्यापार पर वार्ता शुरू होने के खबरों के बीच यह बात कही है। जीटीआरआई के संस्थापक अजय



श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिका की पोस्ट-एफटीए सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के कारण, अमेरिका को किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी फिर से मोलभाव करने का मौका मिल जाता है। बातचीत के दौरान अमेरिकी अधिकारी भारत से घरेलू कानून में बदलाव, नियामकीय सुधार और नीतिगत बदलाव से जुड़े ऐसे मांग कर सकते हैं, जिससे देश की संप्रभुता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा, ःभारत को अमेरिका से बातचीत में न केवल कूटनीतिक

एकतरफा यह तय करता है कि समझौते के तहत भागीदार देश ने अपनी सभी शर्तें पूरी की हैं या नहीं। अमेरिकियों ने प्रक्रिया का अतीत में कई देशों पर अतिरिक्त शर्तें थोपने के लिए इस्तेमाल किया है। श्रीवास्तव ने कहा, ये दोनों कारण व्यापार समझौते से जुड़ी गंभीर अनिश्चितता पैदा करते हैं। अमेरिका समझौते में बाद में बदलाव कर सकता है या अतिरिक्त मांगें रख सकता है। ऐसे में भारत को एफटीए वार्ता में अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है।ः इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाने का ऐलान के मद्देनजर, भारत और अमेरिका के अधिकारी बुधवार से व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू कर रहे हैं।

खेल

आईपीएल के चौथे सबसे युवा कप्तान बने रियान पराग

नई दिल्ली । आईपीएल 2025 के दूसरे मुकाबले में रविवार की रात राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में रियान पराग ने एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने पहली बार कप्तानी करते हुए अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया। 23 साल और 133 दिन की उम्र में वह आईपीएल के चौथे सबसे युवा कप्तान बन गए, और इस सफलता के साथ ही उन्होंने अपने से पहले के दिग्गज श्रेयस अय्यर को पीछे श्रेयस अय्यर ने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी की थी, तब उनकी उम्र 23 साल और 142 दिन थी। इस मैच में कप्तानी करते हुए रियान पराग ने आईपीएल के इतिहास में चौथे सबसे युवा कप्तान बनने का गौरव हासिल किया और श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ दिया।रियान पराग ने अपनी कप्तानी की शुरुआत बड़े आत्मविश्वास के साथ की और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेने में कोई संकोच



साल और 133 दिन है, और वह पहली बार आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं। इससे पहले श्रेयस अय्यर ने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी की थी, तब उनकी उम्र 23 साल और 142 दिन थी। इस मैच में कप्तानी करते हुए रियान पराग ने आईपीएल के इतिहास में चौथे सबसे युवा कप्तान बनने का गौरव हासिल किया और श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ दिया।रियान पराग ने अपनी कप्तानी की शुरुआत बड़े आत्मविश्वास के साथ की और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेने में कोई संकोच

नहीं किया। उनका यह कदम न केवल उनके लिए बल्कि राजस्थान रॉयल्स के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस मैच के बाद से रियान पराग आईपीएल इतिहास के सबसे युवा कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, और यह उनके करियर का एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन अगर बात करें आईपीएल के सबसे युवा कप्तान की, तो यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने 2011 में

आरसीबी के लिए 22 साल 187 दिन की उम्र में कप्तानी संभाली थी। उन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में कप्तानी का रिकॉर्ड बनाया था और इसके बाद से वह लगातार क्रिकेट जगत में एक सुपरस्टार के रूप में चमकते रहे। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में आरसीबी को 2016 में फाइनल तक पहुंचाया, हालांकि उस साल उनका खिताब जीतने का सपना सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया था। रियान पराग, अब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने वाले सातवें

खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले संजू सैमसन, शेन वॉर्न, राहुल द्रविड़, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य राहणे और शेन वॉटसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस टीम के कप्तान रह चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में एकमात्र आईपीएल खिताब जीता था, और अब रियान पराग के नेतृत्व में टीम एक नए मुकाम की ओर बढ़ सकती है। विराट कोहली के बाद अब रियान पराग का नाम सबसे युवा कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गया है। स्टीव स्मिथ, सुरेश रैना, और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी इस सूची में पहले से मौजूद हैं, लेकिन रियान पराग ने अपने पहले ही मैच में कप्तानी के साथ एक नया इतिहास रचा है। विराट कोहली- 22 साल 187 दिन स्टीव स्मिथ- 22 साल 344 दिन सुरेश रैना- 23 साल 112 दिनरियान पराग- 23 साल 133 दिन श्रेयस अय्यर- 23 साल 142 दिन।

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान को मैच के दौरान आया हार्ट अटैक

ढाका । बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल के स्वास्थ्य को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। सोमार को ढाका प्रीमियर लीग (डीपीएल) के एक मैच के दौरान तमीम इकबाल को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीम इकबाल के अनुसार, अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 36 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज तमीम इकबाल सावर के बीकेएसपी में चल रहे ढाका प्रीमियर लीग में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की कप्तानी कर रहे थे। उनकी टीम का मुकाबला शिनेपुकुर क्रिकेट क्लब से था। मैच के दौरान अचानक तमीम इकबाल ने सीने में तकलीफ की शिकायत की। मैदान पर प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद उन्हें आगे के इलाज और जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां हार्ट टेस्ट में पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। क्रिकबाल की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के एमो डॉक्टर ने



बताया, तमीम ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी जांच और ईसीजी किया गया। शुरुआती जांच में कुछ समस्या दिखी, जिसे तुरंत पहचानना मुश्किल था। पहले ब्लड टेस्ट में भी एक समस्या सामने आई। उन्होंने असहज महसूस होने और ढाका वापस जाने की इच्छा जताई थी। डॉक्टर ने आगे जानकारी दी, एक एम्बुलेंस बुलाई गई और जब वह अस्पताल से मैदान की ओर लौट रहे थे, तो उन्हें फिर से सीने में दर्द महसूस हुआ। इसके बाद

उन्हें दूसरी बार अस्पताल ले जाया गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उन्हें फाजिलतुन्नेस अस्पताल में निगरानी में रखा गया है।ः सूत्रों के मुताबिक, तमीम इकबाल का ऑपरेशन किया जा रहा है और उनके हृदय में एक स्टेंट डाला जाएगा ताकि रक्त प्रवाह को सुचारु किया जा सके। इस खबर से बांग्लादेश के क्रिकेट जगत में चिंता की लहर दौड़ गई है और उनके प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।



विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत आवश्यक : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोजपाल मित्र परिषद के कैसर जागरूकता एवं जाँच शिविर का किया शुभारंभ

भोपाल/नवप्रदेश। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाला समय भारत का है। हम फिर से सोने की चिड़िया बनने की राह पर हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, सबसे पहला सुख निरोगी काया है। विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत आवश्यक है। इसके लिए नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी होगी और नियमित जाँच करवानी होगी, ताकि रोगों का समय पर निदान हो सके और प्रसार को रोका जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ज्ञान विज्ञान भवन, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल

में भोजपाल मित्र परिषद द्वारा आयोजित कैसर जाँच एवं जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढीकरण के लिये सतत प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय प्रयासों के साथ निजी सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2003 में प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 17 हो चुके हैं। आगामी 2 वर्षों में 8 नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजना है। इसके अलावा, 12 जिलों में पीपीपी मोड से मेडिकल कॉलेज स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने



भोजपाल मित्र परिषद द्वारा कैसर जागरूकता एवं जाँच शिविर की पहल की सराहना करते हुए कहा कि कैसर की सही समय पर जाँच निदान को सरल बनाती है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

ने कहा कि राइट-टू-हेल्थ के साथ राइट-टू-स्क्रीनिंग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में 30 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों की जाँच के लिए 20 फरवरी से 31 मार्च तक निःशुल्क

निरोगी काया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीपी, सुगर, फैटी लीवर और कैसर की जाँच की जा रही है। उन्होंने उपस्थित युवाओं और प्रबुद्ध जनों से आह्वान किया कि इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इससे अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

निरोगी काया अभियान में की जा रही है निःशुल्क जाँच

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत असंचारी रोगों की स्क्रीनिंग के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों पर जाँच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रोगों की पहचान होने पर त्वरित रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य

केंद्रों, सिविल अस्पतालों अथवा जिला चिकित्सालयों में उपचार प्रारंभ किया जा रहा है। नए मरीजों की पहचान के लिए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के आधार पर असंचारी रोग स्क्रीनिंग एवं पंजीयन का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग के साथ-साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए विभिन्न बीमारियों के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी भी दी जा रही है।

हर संभागीय मुख्यालय में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का प्रयास

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि कैसर के इलाज के लिए शीघ्र ही प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में

%सेंटर-ऑफ़-एक्सीलेंस% स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में अत्याधुनिक उपकरण जैसे ब्रेकी थैरेपी, पेट स्कैन, लीनियर एक्सीलेरेटर आदि की सुविधा होगी तथा पर्याप्त मैनुअल की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क और सजग रहना भी आवश्यक है, ताकि जीवनशैली में सुधार कर स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान दिया जा सके। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण और उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने योग और प्राणायाम को जीवन में अपनाने पर बल दिया।

संक्षिप्त खबरें

सिकल सेल एनीमिया रोग के उन्मूलन के लिए आयुष विभाग प्रतिबद्धता से कार्यरत : मंत्री परमार



भोपाल/नवप्रदेश। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के जन्म दिवस के अवसर पर मंत्रालय में आयुष विभाग अंतर्गत ंधार एवं बड़वानी जिले के सिकल सेल एनीमिया ग्रसित रोगियों के लिए एड ऑन थैरेपी के रूप में आयुर्वेद औषधि वितरण कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारम्भ किया। आयुष मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प, ‘सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत’ को साकार करने करने के लिए गति देने की दिशा में यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश से सिकल सेल एनीमिया नामक जटिल रोग को जड़ से मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रदेश के सिकल सेल एनीमिया ग्रसित नागरिकों को इस जटिल रोग से निदान दिलाने के लिए आयुष विभाग प्रतिबद्धता से कार्यरत है। मंत्री श्री परमार ने आशा व्यक्त करते कहा कि प्रदेश को स्वस्थ एवं निरोगी बनाने में यह कार्यक्रम अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा। मंत्री श्री परमार ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से भी लगातार क्रियान्वयन हो रहा है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि ‘सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत’ के संकल्प की सिद्धि की दृष्टि से राज्यपाल श्री पटेल के सतत् निगरानी में प्रदेश में लगातार कार्य हो रहे हैं। सर्वप्रथम दो जिलों धार एवं बड़वानी में, भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसरण करते हुए आयुर्वेद औषधि वितरण आरम्भ किया गया है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में इस रोग का प्रभाव अधिक है, इस जटिल रोग से प्रभावित नागरिकों को निदान दिलाने के कुत संकल्पित प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री श्री परमार ने कहा कि स्वस्थ एवं निरोगी भारत बनाने में, मध्यप्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अंकित करेगा। इस अवसर पर आयुक्त आयुष श्रीमति उमा आर माहेश्वरी एवं अपर सचिव आयुष श्री संजय मिश्र सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश को निरोगी एवं स्वस्थ प्रदेश बनाना हमारा लक्ष्य

धार एवं बड़वानी जिले के सिकल सेल एनीमिया ग्रसित रोगियों के लिए आयुर्वेद औषधि वितरण कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारम्भ

सिविल सप्लाई कार्पोरेशन की संगठनात्मक संरचना में सुधार का प्रस्ताव तैयार करें

खाद्य मंत्री राजपूत ने संचालक मण्डल की बैठक में दिये निर्देश

भोपाल/नवप्रदेश। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन की संगठनात्मक संरचना (ओ.एस.) में सुधार के लिये प्रस्ताव तैयार करें। इसके लिये कंसल्टेंट की सेवाएँ भी ली जा सकती हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह निर्देश कार्पोरेशन की संचालक मण्डल की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये अधिकारी उपार्जन के केंद्रों का सतत् निरीक्षण करें। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि वे स्वयं भी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

रिक्त पदों की भर्ती जल्द करें

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि कार्पोरेशन में रिक्त पदों की भर्ती जल्द करें। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स में एक्सपर्ट व्यक्तियों को ही नियुक्त करें।



उन्होंने निर्देश दिये कि कार्पोरेशन के लंबित लेखा संबंधी कार्य पूरे कराने के लिये सविदा में लेखापालों की नियुक्ति करें। बैठक में उपार्जन कार्य में लगे कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 की प्रोत्साहन राशि के रूप में एक माह का वेतन देने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 की लंबित प्रोत्साहन राशि के संबंध में भी चर्चा हुई। वरिष्ठ सहायकों के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया गया। मंत्री श्री राजपूत ने कहा

‘कि संचालक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन समय-सोमा में करें।

अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने कार्पोरेशन द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक में आयुक्त खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा, एमडी सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन श्री अनुराग वर्मा सहित संचालक मण्डल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

भोपाल में दत्तक ग्रहण विनियम-2022 पर दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

भोपाल/नवप्रदेश। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में पलाश होटल, भोपाल में दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 एवं 26 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बच्चों के कानूनी और नैतिक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बच्चों के दत्तक ग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल गोद लेने की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाया जाएगा, बल्कि बच्चों को एक उज्ज्वल भविष्य भी

अधीक्षक/प्रबंधक शामिल हुए। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 26 मार्च को शेष जिलों के प्रतिभागी शामिल होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती निर्मला भूरिया ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों के एडॉप्शन से जुड़ी संवेदनाओं को समझने और इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बच्चों के दत्तक ग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल गोद लेने की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाया जाएगा, बल्कि बच्चों को एक उज्ज्वल भविष्य भी

मिलेगा।

गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर जोर

आयुक्त महिला एवं बाल विकास श्रीमती सूफिया फारुकी वली ने कहा कि विभाग दत्तक ग्रहण विनियम-2022 के तहत बच्चों के स्थायी पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ‘नैतिक और कानूनी तरीके से गोद लेना बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। यह न केवल बच्चों को एक सुरक्षित और प्यार भरा घर देता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन

सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।- दत्तक माता-पिता के घरों का समुचित निरीक्षण, उनकी क्षमता का मूल्यांकन और सत्यापन बेहद जरूरी है, इससे बच्चों को सही परिवार मिले। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएआरए की सहायक संचालक सुश्री रूपांशी पांडेय, श्री सुमित भार्गव (जूनियर प्रोफेशनल), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के डॉ. एस. नित्यानंदा (सहायक प्राध्यापक), डॉ. कृपाशंकर चौबे (सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, भोपाल) ने प्रतिभागियों को विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियम-

2022 का उद्देश्य भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अधिक बच्चों को परिवार का प्यार एवं संरक्षण उपलब्ध कराना है। यह नियम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 के तहत लागू किए गए हैं, जो अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्षित बच्चों के पुनर्वास के लिए दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत में दत्तक ग्रहण की पूरी प्रक्रिया का विनियमन, पर्यवेक्षण और प्रोत्साहन करने वाली संस्था है। जो भी दत्तक माता-पिता कानूनी रूप से बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उन्हें सीएआरए के माध्यम से आवेदन करना होता है।

फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने में देश में प्रथम मध्यप्रदेश

भोपाल/नवप्रदेश। फार्मर रजिस्ट्री के तहत फार्मर आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर हैं। प्रदेश में अब तक 72 लाख से अधिक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। फार्मर आई डी बनाने का कार्य राज्यस्व विभाग का अमला किसान भाइयों के सहयोग से विशेष कैम्प लगा कर कर रहा है। प्रमुख सचिव राजस्व श्री विवेक पोरवाल फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने के कार्य की सतत मानीटरिंग कर रहे हैं। आयुक्त भू-अभिलेख श्रीमती अनुभा सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत प्रदेश में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। इसमें प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनायी जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। जिससे किसानों को कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से आसान ऋण प्राप्त करने के साथ विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि, फसल और कृषकों की जानकारी का सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा। इससे भौतिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मध्यम और कमजोर वर्ग के आवासों का निर्माण हाउसिंग बोर्ड की प्राथमिकता- मंत्री विजयवर्गीय

इंदौर में बनेगा आइकॉनिक व्यावसायिक टॉवर, हुकुमचंद मिल परिसर का होगा कायाकल्प

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण से बोर्ड और मजबूत करे अपनी साख

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बैठक में की समीक्षा

भोपाल/नवप्रदेश। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बोर्ड समाज के मध्यम और कमजोर वर्ग के आवासों की आवश्यकता को पूरा करने को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि बोर्ड अपने कामों की गुणवत्ता से आम जनता के बीच में अपनी साख को

और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि बोर्ड अपने प्रत्येक प्रोजेक्ट की गहन समीक्षा करें और इसे नियत टाइम फ्रेम में पूरा किया जाये। मंत्री श्री विजयवर्गीय आज भोपाल में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के निर्माण कार्यों की बैठक में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय शुक्ला भी मौजूद थे। मंत्री श्री विजयवर्गीय द्वारा अगले 2 माह में बोर्ड की पुनः समीक्षा की जायेगी। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि बोर्ड के कॉमर्शियल परिसर के समय पर पूरा होने पर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।



उन्होंने कहा कि बोर्ड की योजनाओं में विभिन्न एजेंसियों के बीच में किसी तरह की देरी होती है, उसे उनके द्वारा दूर करने का ठोस प्रयास किया जायेगा। मंत्री श्री विजयवर्गीय

ने कहा कि बोर्ड जिन आवासीय और व्यावसायिक परिसरों का विकास करता है, भविष्य में वे अच्छी तरह मटेन रहें, इसके लिये मेकेनिजम तैयार किया जाये। उन्होंने

कहा कि जिन परिसरों का विकास बोर्ड द्वारा किया जाये, उनका नामकरण महान हस्तियों के नाम पर किया जाये। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर के हुकुमचंद मिल परिसर में बनने वाला व्यावसायिक टॉवर आइकॉनिक हो, इसका ध्यान रखा जाये। बैठक में बताया गया कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा पिछले 5 वर्षों में 815 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय गया है। हाऊसिंग बोर्ड द्वारा अब तक प्रदेश में 3 लाख 50 हजार से अधिक आवास इकाइयां विकसित की जा चुकी हैं। बैठक में आवासीय, अटल आश्रय, पुनर्धनत्वीकरण (री-डेंसिफिकेशन), पुनर्निर्माण (री-डेवलेपमेंट)) और सु-राज योजना

की समीक्षा की गई। प्रदेश में पुनर्धनत्वीकरण की 106 योजनाएं, जिनकी निर्माण लागत 5 हजार 770 करोड़ रुपये के करीब है, इन पर काम चल रहा है।

अपर मुख्य सचिव श्री संजय शुक्ला ने बताया कि हाऊसिंग बोर्ड की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये रिक्त पदों पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भर्ती किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के परिसर को हरा-भरा रखने के लिये पौध-रोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बोर्ड की मार्केटिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिये भी प्रायवेट एजेंसी का सहयोग का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

